

वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विदेश नीति की चुनौतियाँ

डॉ. अखिलेश कुमार द्विदेदी

शोध-निर्देशक

सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (राजनीति शास्त्र)

रेवती रमण मिश्र शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सूरजपुर

जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

श्रीमती नीलम शुक्ला

शोधार्थी

शोध-छात्रा-राजनीति शास्त्र

शासकीय राजमोहिनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय,

अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)

शोध सारांश :

भारत के राजनेता 2024 का लगभग आधा समय अप्रैल, मई और जून में सात हफ्तों तक चलने वाले आम चुनावों पर ध्यान केंद्रित करके बिताएंगे। लेकिन एक बार जब नतीजे घोषित हो गए, तो भारत की विदेश नीति में ऊर्जा लौट आई और फिर से चुनी गई मोदी सरकार ने कई अहम मुद्दों से निपटने के लिए कदम बढ़ाए। इस लेख में इनमें से चार चुनौतियों पर चर्चा की गई है : चीन के साथ भारत के संबंधों को स्थिर करना; रूस के साथ काम करना; संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी विकसित करना; और एक गतिशील पड़ोस में प्रभाव बनाए रखना। यह तर्क देता है कि साल भर में नई दिल्ली ने प्रत्येक के साथ कुछ प्रगति की, लेकिन उनमें से किसी के साथ भी ठोस प्रगति करने के लिए संघर्ष किया। भारत ने चीन के साथ विवादित सीमा के हिस्से पर सेना को हटाने के लिए एक समझौता किया, लेकिन व्यापक रूप से तनाव कम नहीं हुआ। भारत ने मास्को से फिर से संपर्क किया, लेकिन हिंदू दक्षिणपंथियों की बढ़ती जांच के तहत अमेरिका के साथ संबंधों में एक और जलन पैदा करने की कीमत पर। और भारत ने दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में प्रभाव बनाए रखने और बनाने की कोशिश की, लेकिन उसे महत्वपूर्ण असफलताओं का सामना करना पड़ा, खासकर बांग्लादेश में

मुख्य शब्द :- भारत; भारतीय विदेश नीति; चीन; रूस; संयुक्त राज्य अमेरिका; दक्षिण एशिया आदि।